भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1217

जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में डिजिटल लेनदेन

1217. श्रीमती शांभवी:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत छह वर्षों के दौरान कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रणालियों में पारदर्शिता बढ़ाने में डिजिटल लेनदेन का वर्ष-वार क्या योगदान रहा है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में लेनदेन में डिजिटल परिवर्तन के रूप में टियर-2 और टियर-3 शहरों में डिजिटल भुगतान को अपनाने की दर का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्बाध उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों के कार्यनिष्पादन को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए सरकार के पास क्या तंत्र मौजूद है;

(घ) सरकार द्वारा छोटे व्यवसायों और एमएसएमई को डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने में सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि उनका ग्राहक दायरा बढ़ाया जा सके और दक्षता में सुधार लाया जा सके; और

(ड.) क्या सरकार के पास कर अनुपालन बढ़ाने और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को कम करने में डिजिटल लेनदेन के योगदान पर कोई डेटा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): पिछले छह वित्तीय वर्ष, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25, के दौरान डिजिटल भुगतान लेनदेन का विवरण अनुबंध-I के रूप में संलग्न है। सरकार टियर-2 और टियर-3 शहरों सहित देश में डिजिटल भुगतान को अपनाने की दरों को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), फिनटेक, बैंकों और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है। आरबीआई ने टियर-3 से टियर 6 शहरों, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और जम्मू और कश्मीर में डिजिटल भुगतान स्वीकृति अवसंरचना के अभिनियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2021 में भुगतान अवसंरचना विकास

कोष (पीआईडीएफ) की स्थापना की है। 31 मई, 2025 की स्थिति के अनुसार, पीआईडीएफ के माध्यम से लगभग 4.77 करोड़ डिजिटल टच पॉइंट स्थापित किए जा चुके हैं।

(ग): आरबीआई ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) विकसित किया है। सूचकांक अर्ध-वार्षिक रूप से प्रकाशित होता है और मार्च 2018 को आधार अवधि (सूचकांक = 100) के रूप में आधारित होता है। नवीनतम प्रकाशन के अनुसार, आरबीआई-डीपीआई सितंबर 2024 में 465.33 पर रहा, जो देश भर में डिजिटल भुगतान अपनाने, बुनियादी ढांचे और कार्यनिष्पादन में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है।

(घ): छोटे व्यवसायों और एमएसएमई को अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने और दक्षता में सुधार करने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने में सहायता करने के लिए सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई द्वारा समय-समय पर विभिन्न पहल की गई हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, छोटे व्यापारियों के लिए कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना, ट्रेड रिसीवबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) संबंधी दिशानिर्देश जो एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी दरों पर टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर अपने चालान के संबंध में छूट प्राप्त करने की अनुमति देते हैं और डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का युक्तिकरण शामिल हैं।

(ङ): डिजिटल भुगतान को अपनाने से वित्तीय सेवाओं तक विशेष रूप से अल्पसेवित और असेवित समुदायों के लिए पहुंच में क्रांति आ गई है। यूपीआई जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से निर्बाध, पता लगाने योग्य लेनदेन को सक्षम करके, डिजिटल भुगतान ने व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए एक मजबूत वित्तीय फुटप्रिंट तैयार किया है। ये फुटप्रिंट वित्तीय संस्थानों के लिए वैकल्पिक डेटा प्वाइंट के रूप में कार्य करते हैं, जिससे उन्हें पारंपरिक दस्तावेज़ीकरण की अनुपस्थिति में भी ऋण पात्रता के मूल्याकन करने की अनुमति मिलती है। इसके परिणामस्वरूप, अधिक लोग औपचारिक क्रेडिट चैनलों तक पहुंचने में सक्षम हैं, जो न केवल आर्थिक भागीदारी को सशक्त बनाता है बल्कि औपचारिक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक संस्थाओं को भी भागीदार बनाता है। यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने छोटे विक्रेताओं और ग्रामीण उपयोगकर्ताओं सहित नागरिकों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने, नकदी निर्भरता को कम करने और औपचारिक आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में सक्षम बनाया है।

*****

अनुबंध I

पिछले छह वित्तीय वर्ष के डिजिटल लेनदेन का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	मात्रा (करोड़ में)	मूल्य (लाख करोड़ में)
वित्तीय वर्ष 2019-20	3,401.55	1,619.69
वित्तीय वर्ष 2020-21	4,370.68	1,414.58
वित्तीय वर्ष 2021-22	7,197.68	1,744.01
वित्तीय वर्ष 2022-23	11,393.82	2,086.85
वित्तीय वर्ष 2023-24	16,443.02	2,428.24
वित्तीय वर्ष 2024-25	22,198.15	2,862.12

*****